फतेहाबाद में विपक्ष की एकता भी है 'भारत जोड़ो' का एक राजनीतिक प्रतिफलन

अरुण माहेश्वरी

कल (25 सितंबर) हरियाणा के फतेहाबाद में देवीलाल जी के 109वें जन्मदिवस के 'सम्मान दिवस समारोह' के मंच पर विपक्ष की ताकतों की एकता का अनूठा प्रदर्शन बताता है कि आने वाले दिनों में भारत में सांप्रदायिक फासीवाद के खिलाफ भारत की जनता के एकजुट संघर्ष का जो अंतिम रूप सामने आने वाला है, उसका दायरा किस हद तक व्यापक और गहरा हो सकता है ।

इस मंच पर नीतीश कुमार, शरद पवार, सीताराम येचुरी, तेजस्वी यादव के अलावा शिव सेना के अरविंद सामंत और अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल भी शामिल थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो कांग्रेस दल इस मंच पर उपस्थित नहीं था, वह अनुपस्थित रह कर भी यहाँ पूरी ताकत के साथ मौजूद था। इस मंच के सब नेता इस बात पर एकमत थे कि विपक्ष के एकजुट संघर्ष के मंच में कांग्रेस और वामपंथियों की एक प्रमुख भूमिका होगी। इस बात की खुली ताईद की गई कि नीतीश आदि सोनिया गांधी के संपर्क में हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद ही विपक्षी एकता की आगे की रणनीति की ठोस रूप-रेखा सामने आएगी।

यही बात और भी कई ऐसे क्षेत्रीय दलों के बारे में भी कही जा सकती है, जो अपने-अपने राज्यों में सत्ता में हैं। फासीवाद के प्रतिरोध के इस अखिल भारतीय प्रतिरोध मंच में वे आगे कैसे अपनी भूमिका अदा करेंगे, इसकी साझा रणनीति में उन सबका भी अपना योगदान होगा।

कहना न होगा कि इस मंच के निर्माण

का मुख्य आधार होगा- विभाजनकारी फासीवाद के खिलाफ एकजुट जनतांत्रिक भारत। नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता के इस मंच के राजनीतिक आधार को स्पष्ट करते हुए यही कहा कि बीजेपी अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए हमारे समाज में हिंदू-मुस्लिम विद्वेष पैदा कर रही है, लेकिन यथार्थ में हमारे समाज में ऐसा कोई विरोध है नहीं। इस विद्वेष का जो शोर सुनाई देता है वह चंद उपद्रवी तत्वों की कारस्तानी भर है।

का. सीताराम येचुरी ने भी कहा कि बीजेपी को भारत को, उसके मूलभूत मूल्यबोध को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वह जनता के एक हिस्से को दूसरे से नफ़रत करना सिखा कर अपना लाभ करना चाहते हैं। उनकी यह योजना पराजित होगी। शरद पवार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए बीजेपी को परास्त करना ज़रूरी बताया, तो सुखबीर सिंह बादल ने देश के संघीय ढाँचे की रक्षा के लिए किसान-मज़दूर एकता की बात कही।

हम सभी विपक्ष के दलों की अब तक की भूमिकाओं के इतिहास के कई नकारात्मक पहलुओं के साक्षी रहे हैं। इसके बावजूद फतेहाबाद से उठा व्यापकतम विपक्षी एकता का यह स्वर एक बिल्कुल भिन्न सच्चाई का द्योतक है। यह वही स्वर है, जो प्रगतिशील भारत के हृदय में हमेशा से रहा है और जो आज की नई चुनौती भरी परिस्थिति में राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' से पैदा हो रहे आलोड़न के बीच से मूर्त रूप में सुनाई पड़ रहा है। भारत एक नहीं, अनेक फूलों को मिला कर बना हुआ एक सुंदर गुलदस्ता है, भारत का यही मूलभूत सत्य इस नये स्वर की शक्ति का मूल स्रोत है।

राहुल की इस ऐतिहासिक यात्रा का मुख्य नारा है — वे तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। फतेहाबाद के मंच पर विपक्ष की अनोखी एकता का दृश्य क्या इसी नारे का एक सामयिक राजनीतिक प्रतिफलन नहीं है? जैसे-जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, कर्नाटक में एक जन-ज्वार के रूप में प्रवेश करेगी, विपक्ष की एकता का मंच उसी अनुपात में और प्राणवान होता दिखाई देगा ।

विपक्ष की राजनीति के नाना स्तरों पर आज जो हो रहा है, वह सब एक राजनीतिक प्रक्रिया है, एक प्रगतिशील राजनीतिक चर्वणा । एकजुट भारत के स्थायी भाव के साथ जनतांत्रिक और धर्म-निरपेक्ष राजनीति के अनुभवों की चर्वणा । आरएसएस-मोदी-शाह के माफ़िया राज के खिलाफ विपक्ष की एकता की इसी चर्वणा का एक रूप स्वयं कांग्रेस दल के अंदर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए चल रही चर्वणा के रूप में भी दिखाई दे रहा है। यह एक ध्रुव सत्य है कि आज कोई भी विपक्षी दल अपने अस्तित्व की रक्षा मात्र के लिए ही इस प्रकार की चर्वणा से अछूता नहीं रह सकता है।

अपने आंतरिक संकटों से मुक्ति के लिए ही फासीवाद -विरोधी संघर्ष की राजनीतिक गंगा में डुबकी लगाने के लिए ही उसे अपने अंदर के बहुत सारे कलुष को उलीच कर उनसे मुक्त होना होगा। समय बतायेगा कि जो दल जितना जल्द नई राजनीति के इस सत्य को अपनायेगा, वह उतना ही अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने में सक्षम होगा। अन्यथा उभर रहे एकजुट, जनतांत्रिक और स्वच्छ भारत की नई राजनीति में वह एक म्रियमाण शक्ति से अधिक कोई हैसियत नहीं रखेगा।

हम जानते हैं कि यह वह समय है जब प्रचारतंत्र के सारे भोंपू फिर एक बार इस शोर से आसमान को सर पर उठायेंगे कि - 'आयेगा तो मोदी ही'। चारों ओर आरएसएस के विराट रूप की शान में भजन-कीर्तन के व्यापक आयोजन शुरू हो गये हैं और आगे और होंगे। विपक्ष को तोड़-मरोड़ कर, कंगाल बना कर कुचल डालने के मोदी-शाह के गर्जन-तर्जन की माया के बेहद डरावने दृश्य रचे जायेंगे । और इन सबसे अनेक कमजोर दिल नेक लोगों की धुकधुकी बढ़ेगी, उनमें नई-नई आशंकाओं के बीज पड़ेंगे, उन्हें हिटलर की अपराजेयता के इतिहास-विरोधी डर का ताप भी सतायेगा।

पर इन सबका एक ही उत्तर है —'भारत जोड़ो यात्रा' । अत्याचारों के खिलाफ नागरिकों के स्वातंत्र्य के सविनय अवज्ञा के भाव से प्रेरित एक ऐसी यात्रा जिसने कभी इसी ज़मीन पर दुनिया की सबसे प्रतापी साम्राज्यवादी शक्ति को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था। यह यात्रा कांग्रेस दल के नेतृत्व में चल रही यात्रा होने पर भी भारत के किसानों और मजदूरों, बेरोज़गार नौजवानों और भारत के सबसे अधिक उत्पीड़ित अंश, स्त्रियों के उन सभी संघर्षों का ही ऐसा राजनीतिक मिलन-बिंदु है, जो अपने अंतर में एक नए भारत के उदय के परमार्थ से संचालित है। इस यात्रा के लक्ष्य में मोदी को पराजित करना तो जैसे एक निमित्त मात्र है। भारत की जनता की एकता ही इसका प्रमुख उपादान है। 'मोदी तो हारेंगे ही'।

हम 'भारत जोड़ो यात्रा' के समानांतर सांप्रदायिक फासीवाद के खिलाफ भारत के विपक्ष की व्यापकतम एकता के कांग्रेस, वाम और नीतीश आदि के फतेहाबाद प्रयत्नों के आगे और सुफल की अधीर प्रतीक्षा करेंगे।

मोदी सरकार बड़े कॉर्पोरेट को दोनों हाथ से बांट रही सब्सिडी; न्यायपालिका को रियायतें, ये फ्रीबीज नहीं तो क्या है?

जेपी सिंह

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बड़े कॉर्पोरेट को दोनों हाथ से रेवड़ियां बांट रही है। मोदी सरकार ने वेदांता-फॉक्सकॉन के 38,831 करोड़ की लागत से गुजरात में लगने वाले सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग हब और कर्नाटक में लगने वाले सिंगापुर के आईएसएमसी के 22,900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को 50 फीसदी सब्सिडी देने का फैसला किया है। सरकार की इन्सेंटिव स्कीम के यही दो प्रोजेक्ट पहले लाभार्थी बन गए हैं।

इसी तरह कुछ दिन पहले न्यायपालिका को सरकार ने रेवड़ी बांटी थी केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियम, 1959 (नियम) में और संशोधनों को अधिसूचित किया। अन्य बातों के साथ-साथ, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को उनके जीवनकाल में सेवा देने के लिए एक घरेलू सहायक, एक ड्राइवर और एक सचिव सहायक तैनात किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन घरेलू सहायक और ड्राइवर के हकदार होंगे।

मोदी सरकार ने बुधवार को सेमीकंडक्टर यूनिट और डिस्प्ले मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट के लिए 76,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया। सरकार ने कहा कि यह सब्सिडी इसलिए दी जा रही है ताकि वैश्विक कंपनियां आकर्षित हों। हालांकि मौजूदा आवेदनों को पूरा फायदा मिलेगा।

केंद्र सरकार के इस फैसले की तीखा आलोचना हो रही है। कई लोगों ने इसकी रेवड़ी संस्कृति से तुलना की है। द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित अपने ताजा लेख में स्वामीनाथन एस अंकलेश्वर अय्यर ने लिखा है कि गुजरात में लगने वाले वेदांता सिलिकॉन फैब्रिकेशन प्लांट को दी जाने वाली 50 फीसदी सब्सिडी कुल 80,000 करोड़ की होगी। ये रकम तो मनरेगा मद में दी जाने वाले केंद्र सरकार के कुल आवंटन से भी अधिक है।

सरकार ने बुधवार को कहा था कि कंपनियों को पहले दी जाने वाली वित्तीय मदद को संशोधित कर प्रोजेक्ट की कुल लागत के 50 फीसदी के बराबर कर दिया गया है। पहले भी यह सहायता 50 फीसदी ही थी, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा 12,000 करोड़ थी। लेकिन अब इस पर से यह सीमा हटा दी गई है।

सरकार के इस फैसले पर अर्थशास्त्री सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि वेदांता-फॉक्सकॉन जैसे प्रोजेक्ट सरकार के कुल सब्सिडी प्रावधान का बड़ा हिस्सा हड़प जाएंगे और फिर अन्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। एक और तर्क दिया जा रहा है कि इस तरह सरकार सिर्फ चुनिंदा कंपनियों को ही अपनी प्रोत्साहन योजनाओं का फायदा देगी।

इसी मुद्दे पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर और अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने भी कहा है कि इससे होगा यह कि जब सब्सिडी और प्रोत्साहन वाली योजनाएं बंद हो जाएंगी तो फिर इन कंपनियों को भारत आने या यहां टिके रहने में कोई फायदा नजर नहीं आएगा और वे दूसरे देशों का रुख करेंगी। ऐसे में ये कंपनियां न सिर्फ टैक्स दरों में छूट की मांग करेंगी बल्कि सब्सिडी की सुरक्षा भी मांगेगी।

स्वामीनाथन अय्यर ने भी इसी तरह का सवाल उठाया है। उन्होंने अपने लेख में कहा है कि अगर वेदांता-फॉक्सकॉन की कुल लागत 20 अरब डॉलर है तो उसके हिस्से में तो भारत की 10 अरब डॉलर की कुल सब्सिडी आ जाएगी। उन्होंने पूछा है कि ऐसे में क्या होगा अगर अन्य कंपनियां भी सामने आईं तो फिर उन्हें सब्सिडी देने के लिए पैसा कहां से आएगा?

उद्योगों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि योजना तो उन कंपनियों को मदद देने की है जो सेमीकंक्टर के विभिन्न प्रकारों का भारत में निर्माण या उत्पादन करेंगे। इससे कंपनियों की निर्माण लागत कम होगी और वे नई फैक्टरियां लगाने को प्रोत्साहित होंगे। ऐसे ही एक विशेषज्ञ का कहना है कि इसे इस तरह देखना चाहिए कि इससे भारत एक ताकतवर सेमीकंडक्टर उत्पादक या निर्माता के तौर पर स्थापित होगा और उसकी आयात पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। लेकिन इसी किस्म की कोशिश तो भारत 2017 और 2020 में भी कर चुका है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला था। इंटेल, सैमसंग, टीएसएमसी आदि जैसी कंपनियों ने अभी तक इस दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई है।

केंद्र सरकार ने पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियम, 1959 (नियम) में और संशोधनों को अधिसूचित किया। अन्य बातों के साथ-साथ, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को उनके जीवनकाल में सेवा देने के लिए एक घरेलू सहायक, एक ड्राइवर और एक सचिव सहायक तैनात किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन घरेलू सहायक और ड्राइवर के हकदार होंगे।

सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए पूर्व सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को ड्राइवर और सचिव सहायक प्रदान करने के लिए नियमों में 23 अगस्त को संशोधन किया गया था, लेकिन 26 अगस्त को अधिसूचित नवीनतम संशोधन के अनुसार, इन लाभों को आजीवन कर दिया गया है।

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 की धारा 24(1), 24(2)(ष) और 24(2)(द्ध) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र ने नियम 3क्क में संशोधन किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों से संबंधित है। नियमों में 2022 के संशोधन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति से 5 साल की अवधि के लिए चौबीसों घंटे निजी सुरक्षा गार्ड के अलावा आवास पर चौबीसों घंटे सुरक्षा कवर के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति से 3 साल की अवधि के लिए समान सुरक्षा कवर प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा, एक सेवानिवृत्त सीजेआई सेवानिवृत्ति के बाद 6 महीने के लिए दिल्ली में किराए पर मुफ्त टाइप-ङ्कढ्ढढ्ढ आवास के हकदार होंगे। सीजेआई सहित सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हवाई अड्डों पर औपचारिक लाउंज में प्रोटोकॉल के हकदार होंगे। वे एक आवासीय टेलीफोन और आवासीय फोन/मोबाइल फोन/मोबाइल डेटा/ब्रॉडबैंड के लिए प्रति माह 4200 रुपये तक की प्रतिपूर्ति के भी हकदार होंगे। उपर्युक्त लाभ उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त सीजेआई और न्यायाधीशों को इस हद तक सुनिश्चित करेंगे कि वे पहले से ही किसी भी उच्च न्यायालयों या अन्य सरकारी निकाय से समान लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हों जहां उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार संभाला हो।

दरअसल आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जून में वार्षिक लक्ष्य के 21.2 प्रतिशत को छू गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 18.2 प्रतिशत था। अनुमान है कि 2022-23 के लिए सरकार का राजकोषीय घाटा 16.6 ट्रिलियन रुपये होगा। मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था की यही स्थिति है।

इस बीच 'मुफ्त सुविधाओं यानी फ्रीबीज़' पर बहस चल रही है। हर चुनाव से पहले कई राजनीतिक दल टेलीविजन सेट, इंटरनेट के साथ लैपटॉप, साइकिल, स्कूटर, मासिक पेट्रोल कोटा, सेल फोन और यहां तक कि घी जैसे मुफ्त उपहारों को देने का वादा करते हैं, जिन्हें 'फ्रीबीज़' का नाम दे दिया गया है। यह शब्द 'फ्रीबीज़' मुफ्त में दी गई किसी भी वस्तु/सेवा या सुविधा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि क्या कार्पोरेट्स को और न्यायपालिका को रियायतें 'फ्रीबीज़' हैं या नहीं।